

प्रेषक,

संख्या: 745 / 18(1) / 2006

एन०एस०नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,  
कृषि विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 17 जनवरी, 2007

विषय:- मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर के अधीन राजकीय कृषि बीज भण्डार, कृषि रक्षा इकाई के नव निर्माण हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर के पत्र संख्या-15/सात-स०भू० 30/2006 दिनांक 27 सितम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ग्राम महेशपुर, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर के नान जेड०ए० के खेत खेवट संख्या-17 के खाता संख्या-97, खसरा नम्बर 280 गिन जो श्रेणी-15(2) में दर्ज अभिलेख है, मध्ये  $45 \times 30 = 1350$  वर्ग फुट अर्थात् 0.013 है० भूमि को राजकीय कृषि भण्डार एवं कृषि रक्षा इकाई के निर्माण हेतु वित्त अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-260/वि०अनु०-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के क्रम में कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

जिस परियोजना में लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक गोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो हो।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

- 9- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।
- 10- जी.पी. ड्रॉयू फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- 11- किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आंगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दे।
- 12- यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।
- 13- संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी पौड़ी द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।
- 14- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या -11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 2203 - तकनीकी शिक्षा - आयोजनागत - 00 - 112 - इंजीनियरी / तकनीकी कालेज तथा संस्थान -05- इंजीनियरिंग कालेज घुडदीड़ी (पौड़ी)-00-20- सहायक अनुदान/ अशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
- 15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1367/वि० अनु०-3/2006 दिनांक 21.12.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(राजेंद्र सिंह)  
उप सचिव।

#### संख्या व दिनांक तदीव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
  2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
  3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
  4. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, कालेज इकाई, पौड़ी।
  5. वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग।
  6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
  - ✓ 7. राष्ट्रीय सूचना केंद्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
  8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
  9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(संजीव कुमार शर्मा)  
अनुसचिव।